

सार्वजनिक टैलीफोन प्रदान करने के लिए लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1994-95	50000	47,604
1995-96	105000	31,496
1996-97	75000	56,719

(ग) पूर्वोक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और प्राप्ति के बीच का अंतर निम्नानुसार दिया गया है :-

1994-95	2396
1995-96	73504
1996-97	18281

वर्ष 1997-98 के लिए 83000 का लक्ष्य निर्धारित है ।

गुजरात में बुनकरों को न्यूनतम वेतन

* 314. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्छ में हथकरघा निगम के बुनकरों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को उन्हें औद्योगिक मजदूरों के समतुल्य मानने का निर्देश दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के संबंध में श्रम मंत्रालय के स्थायी आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा):

(क) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नहीं है । श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात सरकार द्वारा हथकरघों में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई है । यद्यपि इस मामले में विस्तृत सूचना इकट्ठित की जा रही है ।

(ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत गुजरात सरकार अपने क्षेत्र में रोजगार के सम्बन्ध में अधिनियम प्रावधानों को कार्यान्वित तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार है । राज्य सरकार द्वारा अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तन मशीनरी की भी स्थापना की गई है । श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता में सुधार लायें ।

Working of local bodies

* 315. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the working of local bodies in the States is being examined by Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, steps taken to check and identify drawbacks in their functioning; and

(d) the steps proposed to be taken to streamline the system?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (d) Yes, Sir. The working of the Panchayati Raj institutions in the country is reviewed from time to time in the meetings of concerned Panchayati Raj Ministers and Secretaries held at the national level. A National Committee of Panchayat Ministers under the Chairmanship of Minister of Rural Areas and Employment has been constituted for the purpose. Several suggestions have been made to the States/UTs to streamline the functioning of Panchayati Raj system. A Southern Regional Conference of the Chairpersons of Zila Parishads at NIRD, Hyderabad was held in June, 1997, to know the working of the P.R. bodies in all the selected Southern States. More recently, the Chief Ministers' Conference was held on 2-8-1997 at New Delhi to review the working of the Panchayati Raj Institutions; where the outstanding issues like devolution of powers/functions and responsibilities upon PRIs, setting up of District Planning Committees and implementation of Reports of the State

Finance Commissions and training to PRIs were discussed; and the Conference recommended to set up two Committees; (a) the Committee of the Panchayats and the Tribal Development Ministers of the eight States from the areas covered under Schedule V of the Constitution, under the Chairmanship of Minister (RA&E) to resolve difficulty if any, in enacting the State legislation expeditiously before cut off date i.e. 23rd December, 1997, and; (b) the Committee of the Chief Ministers to examine the issues regarding devolution of powers, functions and responsibilities upon the PRIs, and to recommend measures to streamline the Panchayati Raj system.

National Highways

*316. SHRI V. RAJAN CHELLA-PPA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total distance of the National Highways, State-wise; and

(b) the length of the roads which have two lanes and four lanes in order to avoid heavy traffic, State-wise?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) and (b) Total length of National Highway in the country, State-wise and details of 2-lane and 4-lane.

S. No.	Name of States	Total Length		
		4 Lane (in Kms.)	2 Lane (in Kms.)	2 Lane (in Kms.)
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	2888	28	2500
2.	Arunachal Pradesh	330	..	20
3.	Assam	2296	..	1714
4.	Bihar	2547	15	1860
5.	Chandigarh	24	8	16
6.	Delhi	72	72	..
7.	Goa	229	..	107